17.32 hrs.

HALF-AN HOUR DISCUSSION

FINANCIAL ASSISTANT TO FOOD-AFFECTED STATES

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up Half-an-Hour Discussion.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, यदि हम देश के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो देश के किसी कोने में हमें अकाल दिखाई देगा, कहीं भूखा दिखाई देगा और कहीं बाढ़ की भयंकरता दिखाई देगी । मैं राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहूंगी । राजस्थान में प्रकृति ने जितना क्रूर उपहास किया है शायद ही कहीं देखने को मिलता हो । दो वर्ष तक भयंकर अकाल और सूखे की स्थिति रही और इस वर्ष वहां इतनी अधिक अतिवृष्टि हुई कि एक तरह कयामत ही आ गई । 17 जुलाई, से लेकर 20 जुलाई तक इतनी अधिक भयंकर बारिश हुई जयपुर और उस के आस पास के इलाके में कि शायद 200 वर्ष का इतिहास का पृष्ठ पलटा जाय तो उसमें इस प्रकार की बारिश के उदाहरण हमें नहीं मिलेंगे । राजस्थान के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं । परन्तु जो जिले अधिक प्रभावित हैं उन का जिक्र मैं करना चाहती हूं । जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी और नागौर जिले अत्यधिक इस से प्रभावित हैं । इस प्रकार की क्षति क्यों हुई, इस का कारण यह है कि बांध और जो पुराने तालाब बने हुए थे वह बारिश अधिक होने की वजह से टूट गए और पानी घरों में आ गया । इसी वजह से असंख्य जानें गईं । कई मनुष्य मरे, कई पशु मरे और कई मकान गिर गए । खड़ी हुई फसल कितनी नष्ट हुई इस का तो अनुमान लगाने पर ही पता चलेगा । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने अपनी रिपोर्ट आप के सामने प्रस्तुत की है, उसमें विस्तृत ब्यौरा दिया गया है । मैं उस विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहती । केवल यह निवेदन करना चाहती हूं कि कुल क्षति जो हुई है वह 400 करोड़ रुपये की है । उस क्षति की वजह से वहां की सारी की सारी अर्थ-व्यवस्था चरमरा गई है, सारा का सारा दिन प्रति दिन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है । यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि कई दिनों तक जयपुर का सम्पर्क दूसरे स्थानों से टूटा रहा । रेल के द्वारा भी, सड़कों के द्वारा भी और वायु सेवा के द्वारा भी । इस तरह से यह इलाका पूरी तरह से तबाही के गर्क में चला गया । रेलवे की कितनी क्षति हुई है इसका पूरी तरह से अनुमान अभी लगाया नहीं गया है परन्तु सारी की सारी पुलियायें उखड़ गईं, सारे रास्ते बन्द हो गए । रेल मंत्री जो राजस्थान आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक महीने में रेल सेवा ठीक कर दी जायेगी परन्तु अभी भी रेल सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ।

इसी प्रकार से जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वह भी सारी की सारी प्रभावित हुई हैं । पुलियायें टूट गईं सड़कें टूट गईं । टेली-कम्युनिकेशन्स की जो सेवाएं थीं वह क्षतिग्रस्त हुईं । राजस्थान के लोग तो पहले से ही प्यासे हैं । प्यास बुझाने के इनेगिने जो साधन थे—ट्यूबवेल, हैण्डपम्प और दूसरे साधन, वह भी सारे के सारे क्षतिग्रस्त हुए । जो ड्रेनेज सिस्टम था वह भी पूर्णतया समाप्त हो गया ।

विशेष कर जयपुर में जो क्षति हुई है उसका अनुमान लगाने पर एक तरह से कम्पकंपी सी आ जाती है, दिल दहल जाता है । वहां के लोगों की दास्तान यदि आप सुनें तो आप द्रवित हो जायेंगे । जयपुर में 817.2 मिलीमीटर वर्षा तीन दिनों में हुई । आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा ? कई गांव बाढ़-

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

आउट हो गए। कुछ फोटोग्राफ* मैंने इकट्ठे किए है जो कि मैं पेश करना चाहूंगी। जयपुर में पुराना गलताजी का तीर्थस्थान पूरा नष्ट हो गया। जयपुर की जो गुलाबी सुन्दरता विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण वहां पर देश के ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं वहां जो कभी पहले गया है वह यदि अब जा कर देखे तो उसको वहां की जागर्फी और नक्शा ही बदला हुआ मालूम होगा। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, झोपड़ियां टूट गई हैं और गन्दा पानी जगह-जगह सड़कों पर भरा हुआ है। जानवर मर जाने के बाद कहीं पर जो दुर्गन्ध आती है वही आपको वहां मिलेगी। गरीब लोगों की सारी झोपड़ियां टूटी हुई है जो कि गरीबी की मजाक उड़ाते हुए उनकी दास्तान सुना रही है जो कि 17 और 20 जुलाई के बीच उनके साथ घटित हुई। उन झोपड़ियों को देखने पर और स्वत: वहां जाने पर मानव हृदय चीत्कार कर उठता है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार बताया गया है कि 37 व्यक्ति मरे हैं। साथ ही कुछ गायब भी हैं जिन्हें अब मरा हुआ मान लिया गया है। सरकार कहती है शायद मर गए हैं। परन्तु जो गैर-सरकारी रिकार्ड हैं उनके अनुसार मरने वालों की संख्या फोर फीगर्स में है। इस प्रकार बहुत मानव क्षति हुई है। जयपुर के अलावा टोंक जिले में एक पूरा का पूरा हिंगवानिया गांव पानी में बह गया। केवल एकाध झोपड़ी या कोई पक्का मकान ही बचा हो। वहां के सारे व्यक्ति मर गए। सरकारी रिकार्ड के अनुसार 32 लोग मरे हैं और 70 लापता हैं। परन्तु इससे भी अधिक लोगों के मरने की सम्भावना है। इसी तरह से सवाई माधोपुर जिले में भयंकर स्थिति पैदा हुई है। बान गंगा और गंभीरी नदी का पानी घरों में घुसने से जानवर साफ हो गए। मनुष्यों की क्षति तो कम हुई है परन्तु उस इलाके में जानवरों के अधिक मरने का अनुमान लगाया गया है।

सभापति महोदय : अगर आपने स्थिति पर काफी प्रकाश डाल दिया है तो आप के पास यदि कोई सुझाव हों तो वे दे दीजिए, ताकि मंत्री जी जवाब दे सकें।

SHRI SATISH AGARWAL (Ajmer): The half-an-hour discussion has been admitted because the answers given to the question were not satisfactory. So, she is justified in narrating the full facts and I support her.

MR. CHAIRMAN: Facts she has narrated. I only said, if she wants certain steps to be taken by the Government, she should point them out.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : इसके अतिरिक्त कोटा जो जिला है, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत अधिक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त वहां पर खड़ी फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने खुशी के साथ उन फसलों को बोया था और आज अगस्त के महीने में लहलहाती फसलें दिखाई देती थी, आज वहां बीरान जंगल दिखाई देता है। आपने पांच करोड के लगभग की सहायता की घोषणा की है। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की, मैं बहुत अधिक आभारी हूं कि इस दुखद समय में भी राजस्थान का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां जा कर के इस बात का जायजा लिया कि वास्तव में कितनी क्षति हुई है और पांच करोड की सहायता दी गई। उस चार सौ करोड की क्षति के सामने यह सहायता बिल्कुल ही नगण्य है। इस प्रकार की अल्प सहायता से उन उजड़े हुए घरों को क्या बसाया जा सकता है, उन नष्ट हुए खेतों को खेती

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the document was not treated as laid on the Table.

योग्य नहीं बनाया जा सकता है, उन सड़कों को, उन पुलों को, उन ड्रेनेज व्यवस्थाओं को, वाटर-वर्क्स की स्कीमें जो नष्ट हो गई हैं, उनको फिर से टीक नहीं किया जा सकता है। मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगी कि 28 अगस्त को आपकी स्टडी टीम भी जा रही है और साथ ही हमारी महान नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत अधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने राजस्थान के दौरे का कार्यक्रम बनाया है। यह हमारे राजस्थान का भाग्य है कि वे वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगी। इस मौके पर मैं माननीय कृषि मंत्री जी और राहत मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने राजस्थान की रिपोर्ट आने के पहले ही वहां की खराब स्थिति को समझ कर पांच करोड़ की जो सहायता दी, वह इमीडियेटली दे दी है, परन्तु आप इस पर जरा विचार कीजिए। जैसा कि आप कह रहे थे कि सारा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक पूरी बात नहीं कहेंगे, तब तक वास्तव में आवश्यकता क्या है; इस के बारे में सदन को भान नहीं हो पाएगा। मंत्री जी को रिकार्ड मिल गए होंगे, इसीलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सहायता को अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यद्यपि 14 जुलाई को हमारे नए मुख्य मंत्री ने शपथ ली थी, केवल तीन दिन ही उन्हें हुए थे, वे मंत्रिमंडल भी नहीं बना पाए थे, उन्होंने 24 घंटे काम करके उस भयंकर स्थिति का हिम्मत के साथ मुकाबला किया। आर्मी की सहायता तीन दिन बाद आ गई थी, क्योंकि जयपुर के सभी रास्ते कटे हुए थे। उस बीच उन लोगों के पास फूड-पैकेट्स पहुंचाने, कपड़ा पहुंचाने और अन्य दूसरी प्रकार की सहायता दी गई उसके लिए हमारी प्रधान मंत्री जी और रिलीफ मंत्री और चीफ-सैक्रेटरी भी एक तरह से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने समय पर लोगों को संभाला। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में कितनी अधिक क्षति हुई है, इसका पूरी तरह से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। यद्यपि चार सौ करोड़ की क्षति हुई है, मकान टूटे है, इस सम्बन्ध में सारी रिपोर्ट आपको मिल गई है, परन्तु संक्षेप में मैं आपको बताना चाहती हूं कि 33430 कैटल मरे हैं, जो कि 334 लाख के बराबर हैं। जो मकान पूर्णतः नष्ट हो गए है उनकी क्षति का अनुमान 95 लाख रूपये है। अल्प-क्षति-ग्रस्त मकानों का नुकसान 41.01 लाख रूपये सरकारी मकान जो क्षतिग्रस्त हुए है उन के नुकसान का अनुमान 3189.25 लाख रूपये, सिंचाई के बांध, तालाब आदि की क्षति का अनुमान 981.72 लाख रूपये, पंचायत समितियों के जो छोटे-मोटे टैंक्स थे वे सब नष्ट हो गए उनकी क्षति का अनुमान 1348.03 लाख रुपये, टयूब-वैल्ज़, हैण्ड-पम्पस आदि की क्षति का अनुमान 296 लाख रूपये, बिजली के तार टूटने से जो क्षति हुई है उस का अनुमान 216.36 लाख रुपये, कृषि की जो क्षति हुई है उसका अनुमान 26143 लाख रुपये, उद्योगों की क्षति का अनुमान 84 लाख रुपये, इस तरह सब की सब क्षति मिला कर 400 करोड़ रुपये है। अब इस 400 करोड़ रुपये की क्षति का मुकाबला हम किस प्रकार करेंगे, आप किस प्रकार से हमें सहायता देंगे — माननीय मंत्री जी, इस के बारे में हमें बतलायें। इस समय राजस्थान सरकार ने अपने पी० डब्ल्यू० डी० के माध्यम से कुछ बस्तियों को, जो बिलकुल उजड़ गई थीं, फिर से बसाने का प्लान बनाया है . . .

सभापति महोदय : अभी आप कितना समय लेंगी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : 5 मिनट ।

सभापति महोदय : यह आधा घण्टे की बहस है, अभी मिनिस्टर साहब को जवाब देना है, उन के बाद 4 सदस्य प्रश्न पूछेंगे . . .

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : दो मिनट और दे दीजिए ।

हमें उन कच्ची बस्तियों को बनाने के लिए टिन-शीट्स चाहियें, सीमेण्ट चाहिए । चूंकि सप्लाई विभाग भी माननीय मंत्री जी के पास है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें अधिक से अधिक सीमेण्ट दीजिए, टिन-शीट्स दीजिए ताकि उन को फिर से बनाया जा सके ।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहूंगी कि राजस्थान की यह दुखान्त दास्तान है इस में सहायता के लिए कई स्वयंसेवी संस्थायें आगे आ रही है । इस वक्त तक 61 लाख रुपया स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किया जा चुका है । मैं इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार और वहां के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी — उन्होंने भी हमारी बहुत सहायता की है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने हम को मकान बनाने के लिए बल्लियां और बांस आदि देने का वायदा किया है । इस समय सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों तथा बाहर की जनता से भी मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जो दुखद बाढ़ आई है उस में आप सब दिल खोल कर सहायता दीजिए । मैं सदन के माननीय सदस्यों से कम से कम एक या दो दिन का वेतन देने के लिए अनुरोध करुंगी ।

मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगी कि पांच करोड़ रुपयों से कुछ नहीं होगा, इस सहायता को तुरन्त अधिक बढ़ाया जाना चाहिए । इस के साथ ही मैं संक्षेप में एक बात और कहना चाहती हूं—जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि बाढ़ के साथ-साथ हिन्दुस्तान के कई कोनों में सूखा है । राजस्थान में भी बाढ़ के साथ-साथ कई जिले ऐसे हैं जहां सूखा पड़ गया है, पानी नहीं गिरा है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ़ । इसलिए बाढ़ सहायता के अलावा अकाल सहायता की भी निरन्तर आवश्यकता होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए ये फोटोग्राफ्स सदन की मेज पर रखती हूं ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने राजस्थान के बारे में जो कहा है उस को सुनकर आपको भी दुख हुआ है, सारे सदन को इस बात का दुख है और सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अचानक बारिश होने से पिछले महीने कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है । चूंकि ये इलाके ऐसे थे जहां आम तौर पर बाढ़ नहीं आती, इस लिए इस तरह की नागरिक हानी मुसीबत के लिए पहले से तैयार नही थे । जयपुर में 841 मिली मीटर बारिश नार्मल से ज्यादा हो गई, टोंक में नार्मल बारिश से 425 मिलीमीटर बारिश ज्यादा हुई, ऐसी हालत में नुकसान होना लाजमी था । सरकार ने जितना कुछ उस के बस में था, फौरन कदम उठा कर लोगो को बचाने की कोशिश की, सहायता भी दी । 1576 गांवों पर अचानक बाढ़ का असर पड़ा और कोई 7 लाख 88 हजार की पापूलेशन इससे असरान्दाज हुई । फ़सलें भी काफी तबाह हुई हैं और 2 लाख 48 हजार हेक्टेयर जमीन में फसलों के नुकसान का अन्दाजा राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे पास पहुंचा है । 143 जानें तलफ़ होने का अब तक ब्यौरा मिला है । 228 के करीब लोगों के गुम होने की रिपोर्ट है और

अब तक उन का पता नहीं लगा है तो दुःख के साथ यही कहना पड़ता है कि शायद वे जानें भी जाया गई हैं। 33 हजार से ज्यादा जानवरों का नुकसान पहुंचा है और 5857 पक्के मकान और 67 हजार से ऊपर कच्चे मकान गिर गये। जितनी राजस्थान सरकार ने मदद मांगी है, उस का मेमोरेण्डम आ चुका है और उस के लिए सेण्ट्रल टीम भाइने के लिए जा रही है। इस से पेश्तर कि उन की रिपोर्ट मदद के लिए आए और उस के ऊपर कोई फ़ैसला होता, भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपये की रकम एकदम रास्थान सरकार को वगैर सेण्ट्रल टीम के विजिट किए कुछ मंजूर कर दी। उस में से राजस्थान सरकार ने काफ़ी सहायता लोगों को दी है। 5 हज़ार रुपये हर एक फैमिली को दिये है, जिस का कोई एडल्ट मेम्बर मर गया हो। उस को इमदाद के तौर पर इतना रुपया दिया गया है। इसी तरह से जिन के मकान गिर गये, उनको 600 रुपये से ले कर 1050 रुपये फी मकान नुकसान के अन्दाजे के मुताबिक दिये हैं। कुछ थोड़ा मकान डेमेज हो गया हो या मकान बिल्कुल गिर गया हो, उसको देखते हुए, लोगों के नुकसान को कुछ पूरा किया है और उन को मुआविजा दिया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कोई 2 हजार हटमैंट्स बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को आबाद कराया जा सके।

सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि ऐसे मौके पर जो एक दम हानि हो जाती है, उस का पूरा मुआवजा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। लोग बेघर हो जाते हैं, जानें भी जाती हैं और यह बाढ़ राजस्थान में ही नहीं आई बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस साल भी इस से काफ़ी नुकसान हुआ है। यह अन्दाजा लगाया गया है कि सारे देश में कोई 8 मिलियन हेक्टेयर जमीन सेलाब से, बाढ़ से मुतास्सिर होती है और करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान सारे देश में फ्लड्स से होता है। कई बार इस से चार-चार गुना नुकसान हुआ है जैसे 1978 में सारे देश के अन्दर फ्लड्स से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 18 मिलियन हैक्टेयर जमीन के ऊपर बाढ़ आई थी और उस के अन्दर नुकसान भी बहुत भारी हुआ सारे देश के अन्दर लेकिन कुछ नार्म्स हैं, कुछ तरीके हैं भारत सरकार द्वारा रिलीफ देने के और यह भी माननीय सदस्य मानेंगे कि बाढ़ से जो नुकसान होता है, उस में सहायता सब से ज्यादा दी जाती है जब कि ड्राउट में और फैमिन में कम सहायता मिलती है। बाढ़ों के नुकसान की 75 फ़ीसदी सहायता, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, उस को भारत सरकार पूरा करती है। राजस्थान सरकार-को रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कितना सहायता मुनासिब समझती है, इस का फ़ैसला जल्दी हो जाएगा। चन्द रोज के अन्दर टीम की रिपोर्ट आ जाएगी। राजस्थान ने 394 करोड़ 33 लाख रुपये की सहायता मांगी है भारत सरकार से और कुछ मार्जिन मनी होती है हर एक स्टेट के पास जो हर साल सातवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दी जाती है। यह भी राजस्थान सरकार के पास 7 करोड़ 74 लाख रुपये थी और 5 करोड़ रुपये और दे दिए गये। हम यह उम्मीद करते हैं कि आयन्दा किसानों की जो भूमि है, उस पर फ़सल होगी।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : बहुत से लोगों के इर्रीगेशन वैल्स और जमीनें खराब हो गई हैं, उन के बारे में भी कुछ करिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : वही करने की बही बता रहा हूं। उसके लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार मदद दे सकेगी वह राजस्थान सरकार को भी देगी। दूसरे

[श्री राव बीरेन्द्र सिंह]

सूबों में भी बहुत बाढ़ आई है। बिहार, यू० पी०, गुजरात चार-पांच स्टेटों में काफ़ी नुकसान हुआ है। वैसे 9–10 स्टेट्स में नुक्सान हुआ है। लेकिन जितना नुकसान 1978 में हुआ था, उतना नुकसान भगवान की दया से इस बार नहीं हुआ है। (व्यवधान) ... मेरा ख्याल है कि आपकी और हमारी दुआओं से हम उस नुक्सान को बचा सकेंगे। जो बुरा वक्त था वह शायद गुजर गया है। दरिया भी उतरने शुरू हो गये है, पानी भी निकला है।

जैसा कि मैंने बार-बार अर्ज किया है कि इस चीज़ का पूरा इलाज, लो लोंग टर्म इलाज जब तक नहीं होगा तब तक यह मुसीबत हर साल आती रहेगी और हमें बर्दास्त करनी पड़ेगी। हमारी दरियाओं में से भारी पानी पूरे साल में वह जाता है। 1440 मीलियन एकड़ फीट पानी वह जाता है जिसमें से 1300 मीलियन एकड़ फीट सिर्फ बरसात के दिनों में बह जाता है। जब तक स्टोरेज की मुनासिब व्यवस्था नहीं होती तब तक यह होता रहेगा। बदकिस्मती से हिन्दुस्तान में बड़े स्टोरेज की जगह नहीं है। इसके लिए हमारे पड़ौसी मुल्क नेपाल से बातचीत चल रही है। समझौते हो गए है, इन्वेस्टीगेशंस हो रही है और हम उम्मीद करते हैं जो दरियाएं ज्यादा तबाही लाती है, उत्तर भारत के अन्दर, उनके बड़े बड़े रिजरवायर का इंतजाम हो जाएगा। अभी तक 130 मीलियन एकड़ फीट को स्टोर करने का इंतजाम हो सकता है और सन् दो हजार तक हम कोशिश कर के 70 मीलियन एकड़ फीट पानी को और स्टोर कर पायेंगे। इस तरह से दो सौ मीलियन एकड़ पानी को हम इस सेन्चरी के आखिर तक स्टोर कर सकेंगे फिर भी 12 सौ मीलियन एकड़ फीट पानी बरसात के दिनों में बहेगा। उस का इलाज अभी दिखाई नहीं दे रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा मैं, उनको यकीन दिलाता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से सचेत है। इस मामले में बराबर हम स्टेट गवर्नमेंट को तैयार रहने के लिए कहते रहते हैं। हमारे अफसर भी वहां जा कर देखते है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, पिछले साल। उसके लिए भी एक अलग सेल कायम हो गया है, इर्रीगेशन मिनिस्ट्री के अन्दर। स्टेट के अन्दर अलग अलग रिलीफ कमिश्नर है। राजस्थान के अन्दर भी अलहिदा रिलीफ कमिश्नर का ओहदा बना दिया गया है ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। हमारे भारत सरकार में भी रिलीफ कमिश्नर का एक ओहदा है। इसका काम यही है कि बाढ़ से मुसीबत आये या दूसरे तरीके से मुसीबत आये तो उसमें लोगों को राहत पहुंचाने का काम हो। सेण्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन भी है और दूसरे महकमे है जो यह देखते है कि कहां कहां बंध लगाये जा सकते है, कहां कहां पर छोटे छोटे बांध खड़े कर के पानी स्टोर किया जा सकता है।

जैसा कि मैने अर्ज किया कि बड़े बड़े रिजरवायर जब तक नहीं बनेंगे तब तक हिन्दुस्तान का छुटकारा इन बाढ़ों से नहीं होगा। छोटे छोटे रिजरवायर बनाने की जितनी गुंजाइश मालूम होती है वह कायम किये जाते है। छोटे छोटे बांधों से 15 मीलियन एकड़ फीट पानी स्टोर किया जा सका है और पांच मीलियन एकड़ फीट के करीब हम और स्टोर कर सकते है जो कि छोटे बांधों और टैंकों में किया जा सकता है। लेकिन यह पानी की बहुत कम तादाद है जिससे कि राहत नहीं मिलेगी। जैसा मैंने अर्ज किया कि बराबर के देश नेपाल से बातचीत चल रही है। जो बड़ी बड़ी दरिया बाढ़ लाती हैं अगर उनका पानी वहां पर रोकने का बन्दोबस्त हो जाए तो उससे इर्रीगेशन भी होगा और पावर जेनरेशन भी होगा।

दरियाओं के अन्दर कुछ सिल्टिंग होती हैं। हमारे दरियाओं के अन्दर और बड़े-बड़े रिजरवायर के अन्दर जो सिल्टिंग होती है उसके बारे में भी नेपाल सरकार से समझौता हो चुका है। एक अर्से के अफोरेस्टेशन का काम हो रहा है।

18.00 hrs.

इसके मुताबिक एफारेस्टेशन नेपाल में भारत सरकार के खर्चे से बन रहे है।

इस प्रकार से बहुत से कदम भारत-सरकार उठा रही है और मै उम्मीद करता हूं कि हाउस इस बात के लिए सहमत होगा कि भारत-सरकार की तरफ से फ्लड की मुसीबत को दूर करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है।

पिछले तीस बरस में जो रुपया फ्लड कण्ट्रोल वर्क्स के ऊपर खर्च हुआ है वह 975 करोड़ रुपया है और अब सिर्फ इस छठे प्लान के अन्दर उन सारे पाच साला प्लान और एनुअल प्लान जो दो थे, उनके मुकाबले मे ज्यादा रकम रखी गई है जो 1045 करोड़ रुपये रखी गई है। इस रुपये से जितना काम आगे बढ़ सकेगा उसको आगे बढ़ाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Now four Members whose names come in the ballot will ask one question each. Minister will reply if there is any new point.

Shri Ajit Kumar Saha.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur): With your permission I will speak in Bengali.

*Mr. Chairman, Sir, with your permission I would like to speak in Bengali.

Mr. Chairman, Sir, the country has gained independence in 1947 and 34 years have gone by since that time and we have yet not been able to control the floods which cause devastation in our country year after year. The hon. Minister just now in replying to the mover of this discussion narrated the Government's policy with regard to flood control and the different things that he proposes to do to control floods in the country. How far these will materialise we do not know? Sir, in the year 1949, Shri Jawaharlal Nehru had formed a Committee comprising of scientists to evolve plans to control floods in the country. In 1954, another Commission called the Mitra Committee was set up and this Commission suggested various measures and out of that the Central Government selected the recommendations of the Commission to construct dam on Damodar river and eventually the DVC was formed. Following this, the Man Singh Committee recommended that Rs. 310 crores should be sanctioned for the DVC project but we have seen that this recommendation was not followed in toto and as a result of this the bunds on DVC could not be constructed as per the desired level and paucity of funds was one of its main causes. The consequences of this was indeed very severe because we found in 1978 there was a devastating flood which caused utter ruination to the 12 districts of West Bengal. Every year we find that the State of Assam, West Bengal, Bihar and U.P. suffer because of floods and this year there was a terrible in Rajasthan about which the mover of this discussion has given a lucide description about the damages caused, lives lost and other losses incurred by people of that State. Last year the National Commission on Flood Control had submitted its report we do not know as yet as to what has happened to their recommendations and how of their recommendations are being implemented. I would like to remind this House that our former Irrigation Minister Shri K. L. Rao, had held talks with the Government of Nepal with a view to controlling floods in Brahamputra and he had also mooted

*The original speech was delivered in Bengali

[Shri Ajit Kumar Saha]

a plan to link Brahmaputra and Ganga which would not only control floods in the region but would also help generate electricity. I would like to know if any further steps have been taken by the Government in pursuance of this proposal of the former Irrigation Minister. It is my personal feeling that recommendations of the Committees and Commissions are not implemented and as a result every year we suffer from floods which cause immense losses of property and human lives. The hon. Minister was just now saying that according to the recommendations of the 7th Finance Commission every State was given margin money and there was no cause of worry because out of this money the States can take suitable measures to control floods or to deal with the flood damages and provide relief. In this context I would like to put a question to the hon. Minister. I would like to know how much money the Finance Commission had recommended for being given to the State Governments which suffer from floods and how much was actually given by the Centre to these States? I say this because the States which are effected by floods regularly had asked for Rs. 205 crores and 63 lakhs for flood protection but the Centre had given to them only Rs. five crores and 56 lakhs. I would like to know if the Minister has anything to say in this regard and how can State Government control floods with such meagre amount?

SHRI R. P. DAS (Krishnagar): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister tried to make us believe that flood is only a natural calamity and it is almost like an earthquake. It is not so. Although it is a natural calamity, yet we cannot but remember that from the very dawn of civilisation, even before that, the people fought against floods and they tried to protect land and property by building big embankments along the rivers. Therefore, the hon. Minister cannot shirk his responsibility by merely saying that flood is only a natural calamity.

At the time of attaining Independence, in 1947, there were 120 km. of embankments along the river Damodar and another 3,500 km. of embankments along various channels in the Gangetic delta of the Sunderbans in West Bengal. In Orissa, there were, in stretches, 1209 km. of embankments along Mahanadi and, in Bihar, there were 150 km. of embankments along both the banks of Gandak. In short, there were about 5280 km. of embankments along different rivers giving protection to about 3 million hectares of land. But with the abolition of zamindari system, there was nobody to look after these embankments. The Government at that time was callous and all the embankments were allowed to decay. As a result of that, the embankments had broken down they had decayed and became out of use.

So, because of that, most of the places, particularly, the Bengal Basin experience floods annually. The lower part of Bengal almost every year comes under flood waters. This time, I am sure, when there are no effective measures taken for controlling the floods, when flood waters from Uttar Pradesh, Bihar and Assam come down through the rivers, the whole of Bengal Basin will be inundated by flood waters. In 1978, three-fourths of the land came under flood waters. In West Bengal, out of 15 districts, 12 districts were affected. This time, as far as the report goes, 5 districts are experiencing floods in West Bengal. I am sure, within a very short time, most probably this month or the following month, the Bengal Basin would be over-flooded.

In view of this, I would like to put a specific question. What was the estimated total damage by floods in the State of West Bengal for the last 10 years at current prices and the annual average. (*Interruptions*). It will be helpful to us if you give figures for the last 10 years. If you like, you can give figures for the last 35 years.

What was the estimated total damages by floods in the State of West Bengal for the last 10 years at current prices and the annual

average? This will be very helpful.; How much money was allocated for flood victims of West Bengal all these years? Was that sufficient in the opinion of; the experts of the Union Government? If not, why higher allocation could not be made available to West Bengal?

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Just today we are discussing flood situation when our scientists have successfully launched APPLE in the space and parhaps our Hon. Minister will take advantage of the APPLE to broadcast his views of the nation that such and such calamity has taken place in India and that India Government has failed to control the floods and the nttural calamities!

This is a great problem to India. A planned programme should be taken up by the Government. I would like to particularly ask: How; much money is given for the flood protection work to the Eastern region States every year? I would like to know particularly the amount given to West Bengal, the region which is affected more, of the lower Ganga region and Midnapore. If so, what allocations are made for 1980-81 and the amount sanctioned for 1981-82.

Eastern region cannot be effectively controlled unless we are able to control the ravages of the Brahmaputra and the rivers which originate in Nepal. So far as Brahmaputra is concerned, already a Flood Contral Board is there but, beyond this, nothing has been done. I would like to know; what positive programmes have been taken up to control the floods.

Crores of rupees have been spent for relief work each year but I think nothing, concrete has been done for controlling the floods. So what are the concrete measures, the positive steps, positive programmes, the Govehnment is taking up for controlling floods in the country so that in the near future floods can he controlled?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Chairman, Sir, I do not like to make a speech. The Hon. Minister in his original answers has given the figures of the damages this year. I do not want to quote. But he has said that it is very difficult for Government of India to build reservoirs to store excess water during the monsoon season. My friends had made suggestions, concrete suggestions but, so far as I remember in the last Lok Sabha, the then Prime Minister Shri Morarji Desai has said that Garland Plan will be taken up to check the flood ravages of our country. I want to know whehher this plan will be taken up in the Sixth Plan. My colleagues also have stated about Assam, West Bengal and U.P. You have also mentioned. These are the States where every year flood damages are there, including loss of lives. I would like to know what is the fate of the plan of linking of the Brahmaputra with the Ganga because that will save Assam and West Bengal from the Brahmaputra floods and at the same it will save the Calcutta Port because in lean months Government will be able to supply 40,000 cusecs of water from Ganga through Bhagirati. I want to know what is the fate of that garland plan mentioned by the then Prime Minister, Shri Morarji Desai—regarding linking of the Brahmaputra with the Ganga.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): Sir, one question as a special case because Jaipur is my constituency which was affected by the unprecedented floods. I want to ask only one question with your parmission.

MR. CHAIRMAN: According to rules, it is not permissible...

SHRI SATISH AGARWAL: As a special case.

MR. CHAIRMAN: But, as a special case, since you represent Jaipur and there have been unprecedented floods, I am permitting you.

SHRI SATISH AGARWAL: I thank the hon. Minister for the assurance that he has given to me to his reply to my letter.

[Shri Satish Agarwal]

While supporting all the facts that have been stated by the hon. lady Member from Chittorgarh, Prof. Nirmala Kumari Shaktawat, I add only this much that the volume and the dimension of the problem are much more. I would suggest that you call a meeting of all Members of Parliament who are interested or whose districts have been affected for an across-the-table discussion with you and for giving certain suggestions because we do not want to politicise the issue; we have certain suggestions to make. I do not want to make them here. The main problem in the Jaipur district—I have come from Jaipur only today—is levelling of the land where 10 to 20 feet of additional land has been left deposited over the fields on account of floods. I want to know whether Government will provide the necessary assistance in the form of tractors and bulldozers for this purpose. Some people from Bombay have come and they are doing the job. The main demand of the people in the Jaipur region is this: they do not want doles, they want the land to be levelled and wells to be cleaned. I want to know whether Government will make adequate provision and arrangements for levellig of the lands and cleaning of the wells thereby restoring operation of pumpsets.

You have stated that you will provide 75 per cent of assistance so far as flood relief is concerned, Naturally, Rajasthan should be given immediate assistance without waiting for the report of the Team; against the damages worth Rs. 400 crores, at least Rs. 200 crores should be given. Immediately Rs. 100 crores should be advanced as an interim relief. In addition, a National Calamity Fund should be formed at all-India level like Group Insurance cheme to which every State contributes and the beneficiaries are the States affected.

RAO BIRENDRA SINGH: I have noted the suggestion of the hon. Member from Jaipur. It is not possible for me to give any assurance on matters like this because, after all, we have been following certain norms and procedures, so far, and any deviation from any norms that have been followed upto this time cannot be made without consultation with the Finance Ministry—maybe, I have even to go to the Cabinet for this purpose. But I have no objection to the suggestion of the hon. Member that I call a meeting of the hon. Members from Rajasthan. They are most welcome and I will be glad to discuss with them, and I will put across to my other colleagues and see what more can be done for Rajasthan.

Some of the hon. Members who spoke were interested in getting more information about West Bengal. In fact, they have themselves given most of the information. Probably they know more about their own region than I am in a position to state now.

With regard to the Sundarbans area, the problems are specific because this is the area where sea-water comes in. The problems is to store fresh water for the people, for the cattle and for the crops also. There is a research project under our Soil Salinity Research Institute at Karnal—I.C.R. We are putting up embankments for storage of fresh water and to keep the sea-water from entering this area. This consits of islands—Sunderbans area—and there is a special problem. We are trying to deal with the problem. He wanted to know about the margin money placed at the disposal of various States. I do not think you would have the time for me to state. But, they will be glaid to know that the margin money allocated to West Bengal is the highest in the country. Rs. 13.16 crores of margin money is allocated every year. No other State has got this amount of money. So, West Bengal has already got special considerations. I do not see that there has been any partiality shown to West Bengal. I say that the case of West Bengal has been properly looked after. One hon. Member wanted to know the outlay for the flood control

works during the Sixth Plan. For West Bengal, it is Rs. 200 crores during the Sixth Plan. I can also give the figures for the North-Eastern region. I do not think they are much interested. (*Interruptions*) Let them not react to what I have said. I know that they are interested in West Bengal only.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: No. We are interested for the whole country.

RAO BIRENDRA SINGH: I have already given that—Rs. 1,045 crores. Do you want break-up for all the States?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

RAO BIRENDRA SINGH: For Bihar it is Rs. 158 crores, for U.P. it is Rs. 132 crores and for the Arunachal Pradesh it is Rs. 100 crores during the Sixth Plan Any other States in which you are interested?

MR. CHAIRMAN: They want the figure for Assam.

RAO BIRENDRA SINGH: It is Rs. 22.40 crores for Assam. I have already said as far as Rajasthan is concerned. The total outlay in the Sixth Plan for Rajasthan comes to Rs. 17.75 crores. But, Rajasthan is not a flood prone area. I hope you would agree there. Rajasthan is mostly dry area.

SHRI SATISH AGARWAL: It is now in floods.

RAO BIRENDRA SINGH: We have about 40 million hectares of flood prone area in the country. Out of that, during the last thirty years we had been able to treat only about 11 million hectares. I can see the magnitude of the problem. Nearly one-fourth of the area only so far has been treated and three-fourth still remains.

West Bengal wanted to know the allocation for 1980-81. It was Rs. 32 crores for this year but for the current year the outlay approved by the Planning Commission is Rs. 30.86 crores for West Bengal. I think most of their points have been covered.

MR. CHAIRMAN: Now we adjourn to meet again tomorrow at 11 A.M.

8.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 25, 1981/Bhadra 3, 1903 (Saka)

GMGIPND—M—1446 L. S.—890